



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2001/भाद्र 26, 1923

No. 245]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2001/BHADRA 26, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2001

सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार प्रयोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतानों और पत्तन न्यासों द्वारा विलंबित धन वापसियों पर दंडात्मक ब्याज निर्धारित करने से संबंधित अपने 4 फरवरी, 2000 के आदेश में (16 मई, 2001 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से संशोधित) संशोधन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य

आदेश

(अगस्त, 2001 के 30वें दिन पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने 4 फरवरी, 2000 को प्रयोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतानों और पत्तन न्यासों द्वारा विलंबित धन वापसियों पर 24% का समान दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में एक आदेश पारित किया था।

2. हमने समान ब्याज दर को अपनाने के बारे में भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) के मतों और कुछ पत्तन न्यासों की टिप्पणियों पर विचार करके और दंडात्मक ब्याज दर को 24% वार्षिक से घटाकर 18% वार्षिक करने का निर्णय किया था और 16 मई, 2001 को इस आशय का एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 4 जून, 2001 को अधिसूचित किया गया था।

3. मुरगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) ने अब पत्तन प्रयोक्ताओं को बिल प्राप्ति की तारीख से 7 दिन की अनुग्रह अवधि दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात्, एमओपीटी ने अपने सुझाव में संशोधन करके पत्तन प्रयोक्ताओं को बिल प्राप्ति की तारीख से '7 दिन' के स्थान पर '7 स्पष्ट कार्य दिवस' की अनुग्रह अवधि दिए जाने का सुझाव दिया है। एमओपीटी के इस प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा इससे पूर्व सभी महापत्तन न्यासों द्वारा समान ब्याज दर अपनाने के लिए विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज कम करने के प्रस्ताव के साथ विचार किया गया था। तब एमओपीटी के दिए गए सुझाव पर सभी अन्य महापत्तनों से भी विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया था, ताकि एकसमान निर्धारण किया जा सके।

4.1. एमओपीटी के प्रस्ताव को सभी महापत्तनों को टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है :

#### विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (सीपीटी)

- (i) अनुग्रह अवधि बिल प्राप्ति की तारीख के स्थान पर बिल प्रस्तुत करने की तारीख से केवल 7 दिन रखना उचित होगा, जैसा कि वाणिज्यिक लेनदेनों में आम तौर पर होता है।
- (ii) दंडात्मक ब्याज की वसूली के प्रयोजन से प्रयोक्ता को बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 7 दिन की अवधि रखने के सुझाव पर विचार किया जाए।

#### कांडला पत्तन न्यास (केपीटी)

- (i) 7 दिन की अनुग्रह अवधि की गणना एमओपीटी द्वारा सुझाए गए पत्तन प्रयोक्ताओं को बिल प्राप्ति की तारीख से करने के बजाय बकाया की सूचना जारी करने की तारीख से की जाए।
- (ii) यदि बिल प्राप्ति की तारीख पर विचार किया जाता है तो या तो पत्तन को उसका सत्यापन करना होगा जो एक नीरस काम है या फिर पत्तन को पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा सूचित तारीखों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो उचित नहीं है।

#### कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी)

- (i) यदि पत्तन प्रयोक्ताओं को बिलों पर कार्यवाही के लिए 7 दिन की अनुग्रह अवधि दी जाती है तो एमओपीटी को भी धन वापसियों की कार्यवाही के लिए समान अवधि देनी होगी।
- (ii) यदि एमओपीटी के मामले में अनुग्रह अवधि देना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो यही सिद्धांत सभी अन्य महापत्तनों पर भी लागू करना होगा।
- (iii) सीपीटी ने पहले समयावधि को 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का सुझाव दिया था। यदि दोनों पक्षों के लिए 7 दिन की अनुग्रह अवधि अनुमोदित की जाती है तो कुल समयावधि 20 दिन के स्थान पर 27 दिन होगी। हम एक बार फिर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और दोनों पक्षों के लिए समयावधि 30 दिन करने का अनुरोध करते हैं।
- (iv) विलंबित भुगतान अथवा धन वापसी पर ब्याज वसूल करने का प्रयोजन संभवतः अवसर लागत की पूर्ति करने के लिए है, अर्थात् यदि देनदार द्वारा धन तत्काल जमा कराया जाता है तो लेनदार धन का उपयोग कर कुछ राशि अर्जित कर सकता है। चूंकि वर्तमान बचत बैंक ब्याज न्यूनतम दर पर है, इसलिए हम महसूस करते हैं कि दंडात्मक ब्याज इसके बराबर होना चाहिए। हम इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और 4.5% वार्षिक दर पर दंडात्मक ब्याज पुनः निर्धारित करने का अनुरोध करते हैं।

#### चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

- (i) सीएचपीटी ने पहले भी इस बात पर जोर दिया था कि अधिक राशि की वापसी महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 55 द्वारा शासित है, जिसमें विलंबित वापसियों के लिए ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।
- (ii) दंडात्मक ब्याज से संबंधित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के 4 फरवरी, 2000 के आदेश को केवल पत्तन द्वारा विलंबित धन वापसियों के लिए और पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज को शामिल करने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 55 में उपर्युक्त संशोधन करने के पश्चात ही लागू किया जा सकता है।
- (iii) उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह अपने 4 फरवरी, 2000 के आदेश पर पुनर्विचार करे।
- (iv) चूंकि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 में पूर्व भुगतान पर जोर दिया गया है, इसलिए पत्तन प्रयोक्ताओं को 7 स्पष्ट कार्य दिवस की अनुग्रह अवधि देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 का उल्लंघन होगा।

**पारावीप पत्तन न्यास (पीपीटी)**

- (i) प्रयोक्ताओं द्वारा संभावित प्राप्त सेवाओं के लिए अग्रिम राशि जमा की जाती है।
- (ii) जलयान संबंधी प्रमारों के लिए, अनुमानित अग्रिम जमा राशि से अधिक देय राशि का जहाज के चालन की अनुमति दिए जाने से पूर्व भुगतान करना होता है।
- (iii) घाटशुल्क से मित्र कार्गो संबंधी प्रमारों के लिए जैसे प्लॉट किराया, रेलवे, नौमरण, यदि कोई हो, तो अनुमानित अग्रिम जमा राशि से अधिक राशि देय हो तो बिल प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोक्ता को देयों का भुगतान करने के लिए बिल की तारीख से 7 दिन का समय दिया जाता है, ऐसा न करने की स्थिति में ब्याज वसूल किया जाता है। घाटशुल्क देयों के बीच के अन्तर का, यदि कोई हो, तो भुगतान जहाज के चालन की अनुमति दिए जाने से पूर्व करना होता है।

**न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)**

दंडात्मक ब्याज प्रोद्भूत प्रमारों की सूचना के जारी होने की तारीख अथवा बिल जारी होने की तारीख से जो भी पहले हो, 10वें दिन से अधिक विलंब के लिए वसूल किया जाए।

**तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)**

- (i) पत्तन प्रमार महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 और 65 के उपबंधों के अधीन आते हैं। इन धाराओं में पत्तन प्रमार अदा करने के लिए 7 दिन की अनुग्रह अवधि देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त धारा के अधीन आने वाले प्रमारों के लिए 7 दिन की अनुग्रह अवधि देना अधिनियम के उपबंध के विरुद्ध होगा।
- (ii) जो प्रमार महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 और 65 के उपबंध के अधीन नहीं आते उनकी माँग अदा करने के लिए पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तव रूप में अपेक्षित अनुग्रह अवधि का निर्णय करने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर समीक्षा की जाए। उक्त धाराओं के अधीन न आने वाले प्रमारों के लिए 7 दिनों की संवृत्त अनुग्रह अवधि न दी जाए।

**मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)**

- (i) पहले एमबीपीटी में बिलों/माँग सूचनाओं के भुगतान की अनुग्रह अवधि देने की व्यवस्था थी। यह सभी बिलों के लिए 15 दिन और जलयान संबंधी प्रमारों के मामले में 30 दिन थी। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के 4 फरवरी 2000 के आदेश के कार्यन्वयन के पश्चात्, उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बिलों का तत्काल अगले दिन भुगतान करना होता है और जलयानों को दी जाने वाली सेवाओं के मामले में ब्याज के भुगतान से बचने के लिए भुगतान जलयानों के नौचालन के अगले दिन अदा करना पड़ता है।
- (ii) यह महसूस किया गया है कि बिल के भुगतान के लिए कुछ अनुग्रह अवधि देना आवश्यक है। पत्तन प्रयोक्ता द्वारा बिल प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवस देने का एमओपीटी का सुझाव क्लेशप्रद होगा, क्योंकि इस बीच आने वाले रविवारों और बैंक अवकाश दिवसों के मद्देनजर हर समय कार्य दिवसों की संख्या पर नज़र रखना आवश्यक हो जाएगा।
- (iii) अनुग्रह अवधि साधारण और बिल/माँग सूचना की प्राप्ति की तारीख से कैलेंडर दिनों के रूप में परिभाषित होनी चाहिए। यह महसूस किया गया है कि अनुग्रह अवधि बिल/माँग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 कैलेंडर दिवस होनी चाहिए।

4.2. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी महापत्तनों से, संदर्भित मुद्दे पर 16 जुलाई, 2001 तक अपनी टिप्पणियाँ भेजने का अनुरोध किया गया था और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि यदि निर्धारित तारीख के अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि पत्तन को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

5. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र सूचना और पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :

- (i) सीएचपीटी ने महापत्तन न्यास अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के भीतर दंडात्मक ब्याज निर्धारित करने के लिए इस प्राधिकरण की योग्यता के बारे में विधिक आधारों पर कुछ आपत्तियों की हैं। इस मुद्दे का समाधान इस प्राधिकरण द्वारा पहले ही 19 जुलाई, 2000 के अपने आदेश में (कलकत्ता पत्तन न्यास के मामले में) हल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, इस मुद्दे पर यहाँ दुबारा चर्चा नहीं की गई।
- (ii) इस प्राधिकरण के 4 फरवरी, 2000 के आदेश (16 मई, 2001 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से संशोधित) का आशय पत्तन प्रयोक्ताओं के लिए स्तरीय भुगतान स्थिति उपलब्ध कराना और दोनों ओर से देय दंडात्मक ब्याज में एकरूपता निर्धारित करना है। इस प्रयोजन से, दंडात्मक ब्याज की एकसमान दर निर्धारित की गई है जो पत्तन न्यासों द्वारा विलंबित धन वापसियों एवं प्रयोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतानों पर लागू है। उल्लेखनीय है कि प्रयोक्ताओं के मामले में जहाँ अपने देयों को अदा करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, वहाँ धन वापसियों करने के लिए पत्तनों को 20 दिन का निश्चित (लीड) समय दिया गया है। यह विभेदीकरण इस तथ्य के अनुसार किया गया है कि महापत्तन न्यास अधिनियम में प्रयोक्ताओं को पत्तन सेवाएँ प्राप्त करने से पूर्व अथवा पत्तन निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, लागू प्रभार अदा करने होते हैं।
- (iii) जैसा कि एमओपीटी के प्रस्ताव और पीपीटी द्वारा दी गई टिप्पणियों में कहा गया है कि कुछ सेवाएँ हैं, जिनके लिए बिल प्रचालन के बाद बनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में, भुगतान करने के लिए प्रयोक्ताओं को कुछ निश्चित समय देने की आवश्यकता है। एमबीपीटी की यह टिप्पणी कि वह इस प्राधिकरण के 4 फरवरी, 2000 के आदेश के कार्यान्वयन से पूर्व बिलों के भुगतान के लिए प्रयोक्ताओं को अनुग्रह अवधि दे रहा था, इस संदर्भ में प्रासंगिक है।  
  
प्रयोक्ताओं द्वारा बिलों के भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि, यदि कोई दी गई हो, उन मामलों तक सीमित होगी जहाँ पत्तनों द्वारा प्रचालन के बाद बिल दिए जाते हैं। यह उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ महापत्तन न्यास अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट सेवाएँ प्राप्त करने/पत्तन न्यास की संपत्तियों का प्रयोग करने से पूर्व भुगतान करना पड़ता है अथवा जहाँ प्रभारों का अग्रिम भुगतान दरों के मान में शर्त के रूप में निर्धारित है।
- (iv) अधिकांश महापत्तन प्रयोक्ताओं को अनुग्रह अवधि देने के एमओपीटी के प्रस्ताव से सहमत हैं।  
  
पीपीटी और केपीटी द्वारा यथा उल्लिखित, प्रयोक्ताओं द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से अनुग्रह अवधि देना बलेशप्रद होगा, क्योंकि पत्तनों द्वारा ऐसा विवरण प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इन पत्तनों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, पत्तनों द्वारा ऐसे बिलों को देने की तारीख से अनुग्रह अवधि की गणना अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है।
- (v) एमओपीटी ने अपने पूर्ववर्ती प्रस्ताव में संशोधन करके यह सुझाव दिया है कि अनुग्रह अवधि की गणना केवल कार्य दिवसों के रूप में की जाए। इस संबंध में एमबीपीटी की टिप्पणी प्रासंगिक और युक्तिसंगत है। सरलता के लिए, अनुग्रह अवधि कार्य दिवसों के स्थान पर कैलेंडर दिवसों के रूप में निर्धारित की जाए। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि धन वापसियों के लिए पत्तन न्यासों को अनुमत निश्चित (लीड) केवल 20 दिन है, न कि 20 कार्य दिवस।

- (vi) एमओपीटी ने प्रयोक्ताओं द्वारा बिल प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अनुग्रह अवधि का प्रस्ताव किया है। चूंकि अब अनुग्रह अवधि की गणना पत्तनों द्वारा बिल दिए जाने की तारीख से शुरू करते हुए कैलेंडर दिवसों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है, अतः एमओपीटी और एनएमपीटी के सुझाव के अनुसार 10 दिन की अनुग्रह अवधि देना उचित होगा।
- (vii) अनुग्रह अवधि के बारे में सीपीटी की समझ सही नहीं है। वापसी के दावों की प्रक्रिया के लिए पत्तनों को कोई अनुग्रह अवधि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मामलों में 20 दिन का लीड-समय पहले से ही निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, सीपीटी का तर्क कि दंडात्मक ब्याज अवसर लागत के लिए है और इसलिए यह बचत बैंक खाते की ब्याज दर के समान होना चाहिए, पूर्णतः भ्रामक है। दंडात्मक ब्याज समय से भुगतान/वापसियों सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय है और इसलिए ब्याज दर ऐसे स्तर पर होनी चाहिए जो वास्तव में धूककर्ताओं के लिए शास्ति का कार्य करे।

दंडात्मक ब्याज निर्धारित करने का भुदे का पहले ही समाधान किया जा चुका है और इस प्रकार पहले से निर्धारित दर की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6.1. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण 4 फरवरी, 2000 के अपने आदेश (16 मई, 2001 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से संशोधित) के पैरा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारण को शामिल करने का अनुमोदन करता है : -

- "(iv) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब की गणना पत्तन न्यासों द्वारा बिल दिए जाने की तारीख से केवल 10 दिन बाद से की जाएगी। परंतु, यह उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट सेवाओं/पत्तन न्यासों की संपत्तियों का उपयोग करने से पूर्व भुगतान करना पड़ता है और/अथवा जहाँ प्रभारों का अग्रिम भुगतान दरों के मान में शर्त के रूप में निर्धारित है।"

6.2. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना के तत्काल पश्चात प्रभावी होगा।

3.3. सभी महापत्तन न्यास उपर्युक्त निर्धारण को समाविष्ट करने के लिए अपनी दरों के मान में उपयुक्त परिवर्तन करेंगे।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/IV/143/2001/असा. ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2001

No. TAMP/8/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends its Order dated 4 February, 2000 (partially amended by Order dated 16 May, 2001) relating to fixation of penal interest on delayed payments by the users and delayed refunds by the Port Trusts as in the Order appended hereto.

2876 61/241-2

## SCHEDULE

Case No. TAMP/5/2000-Genl.**ORDER**

(Passed on this 30th day of August 2001)

This Authority had passed an Order on 4 February 2000 relating to imposition of 24% penal interest equally on delayed payments by users and delayed refunds by the Port Trusts. This Order was notified in the Gazette of India extraordinary on 23 February 2001.

2. We had considered the views of the Indian Ports Association (IPA) and comments of some of the Port Trusts about adoption of a uniform interest rate and decided to reduce the penal interest rate from 24% per annum to 18% per annum and passed an Order to that effect on 16 May 2001. This Order was notified in the Gazette of India on 4 June 2001.

3. The Mormugao Port Trust (MOPT) has now submitted a proposal to grant 7 days as a grace period from the date of receipt of the bill to the port users. Subsequently, the MOPT has revised its suggestion to grant '7 clear working days' instead of '7 days' as a grace period to the port-users from the date of receipt of the bill. The proposal of the MOPT was earlier considered by this Authority along with the proposal for reducing penal interest on delayed payments for a uniform common adoption by all the Major Port Trusts. It was then decided to consult all the other Major Ports also on the suggestion made by the MOPT so that a uniform prescription could be made.

4.1. The proposal of the MOPT was circulated to all the Major Port Trust for comments. The comments received are summarised below:

**Visakhapatnam Port Trust (VPT)**

- (i). It will be appropriate to keep the grace period only as 7 days from the date of raising the bill, instead of date of receipt of the bill which is being followed generally in commercial transactions.
- (ii). The suggestion of keeping 7 days period from the date of raising of the bill on the user for the purpose of collection of penal interest may be considered.

**Kandla Port Trust (KPT)**

- (i). The grace period of 7 days shall be counted from the date of issue of outstanding notice to the port user instead of from the date of receipt of bill by the port user as suggested by the MOPT.
- (ii). If the date of receipt of bill is considered, either the Port has to verify it, which is tedious; or, the port has to rely on the date intimated by users, which is not advisable.

**Calcutta Port Trust (CPT)**

- (i). If a grace period of 7 days is allowed to port users processing the bills, the MOPT shall also be allowed the same period for processing refunds.
- (ii). If it is accepted in principle to allow grace period in case of the MOPT, the same principle shall be extended to all other Major Ports.
- (iii). The CPT had earlier suggested to increase the time limit from 20 to 30 days. If the 7 days grace period is approved to both parties, the total time period will be 27 days instead of 20 days. We once again request to re-consider the decision and to increase the time period to 30 days for both the parties.

- (iv). The purpose for charging the interest on delayed payment or refund is probably to make good the opportunity cost i.e. if the money had been deposited forthwith by the debtor, the creditor could have earned some amount by utilising the money. Since the present Savings Bank interest is the lowest rate, we feel that the penal interest must be equal to this. We request to reconsider the decision and refix the penal interest rate at 4.5% per annum.

#### **Chennai Port Trust (CHPT)**

- (i). The CHPT has already stressed the point that refund of excess amount is governed by Section 55 of the MPT Act in which there is no provision for payment of interest for delayed refunds.
- (ii). The Order of the TAMP dated 4 February 2000 relating to penal interest can be given effect only after Section 55 of the MPT Act are suitably amended to include interest for delayed refunds by the Port and delayed payments by the port users.
- (iii). In view of above reasons, the TAMP is requested to review the Order dated 4 February 2000.
- (iv). Since Section 58 of the MPT Act lays emphasis on prepayment, the question of allowing 7 clear working days as grace period to the port users does not arise as it will be in contravention of Section 58 of the MPT Act.

#### **Paradip Port Trust (PPT)**

- (i). Advance deposits are made by the users for the services likely to be obtained.
- (ii). For vessel related charges, any due payable over and above the assessed amount of advance deposit is payable before the ship is allowed to sail.
- (iii). For cargo related charges other than wharfage, like plot rent, railway, stevedoring, if any, amount is due over and above the assessed amount of advance deposit, then a bill is raised and the user is allowed 7 days time from the date of the bill to clear the dues, failing which, interest is levied. The differential wharfage dues, if any, is cleared before the ship is allowed to sail.

#### **New Mangalore Port Trust (NMPT)**

The penal interest may be charged for delay beyond the tenth day from the date of issue of intimation of the accrual of charges or date of issue of the bill, whichever is earlier.

#### **Tuticorin Port Trust (TPT)**

- (i). The Port charges which are covered under the provision of the Sections 58 and 65 of the MPT Act. There is no provision in these Sections to give grace period of 7 days to pay the Port charges. Therefore, extension of grace period of 7 days for the charges covered under the said Section will be ultra-vires of the provision of the Act.
- (ii). The Charges which are not covered under the provision of the Sections 58 and 65 of the MPT Act may be reviewed on a case to case basis to decide the grace period genuinely required by the port users to pay the demand. A blanket grace period of 7 days may not be given for the charges not covered under the said Sections.

**Mumbai Port Trust (MBPT)**

- (i). Earlier, at the MBPT there was a system of granting grace period of payment of bills/demand notice. This was 15 days for all bills and 30 days in case of vessel related charges. After implementation of the Order of the TAMP dated 4 February 2000, the bills in respect of services provided are required to be paid immediately the next day, and in case of services to vessels, the following day of the vessels' sailing to avoid payment of interest.
- (ii). It is felt that grant of some grace period for payment of the bill is warranted. The suggestion of the MOPT to grant 7 working days from the date of receipt of bill by the port user will be cumbersome as it will necessitate keeping track of number of working days every time in view of Sundays and Bank holidays falling in between.
- (iii). The grace period needs to be simple and defined in terms of calendar days from the date of receipt of bill/demand notice. It is felt that the grace period may be 10 calendar days from the date of receipt of bill / demand notice.

4.2. It is relevant here to mention that all the major ports were requested to furnish their comments on the issue in reference by 16 July 2001 with a clear stipulation that it would be presumed that the Port had no comments to offer if reply was not received within the stipulated date.

5. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and with reference to the comments received from port trusts, the following position emerges:

- (i). The CHPT has raised certain objections on legal grounds about the competence of this Authority to prescribe penal interest within the existing provisions of the MPT Act. This issue has already been settled by this Authority in our Order dated 19 July 2000 (in respect of the Calcutta Port Trust). That being so, the issue is not discussed again here.
- (ii). The intention behind this Authority's Order dated 4 February 2000 (partially amended by Order dated 16 May 2001) is to provide a level-paying condition for port-users and to prescribe uniformity in penal interest payable both ways. Towards this end, a uniform rate of penal interest has been prescribed which is applicable on delayed refunds by Port Trusts as well as on delayed payments by users. It is noteworthy that a lead-time of 20 days has been allowed for Ports to make refunds whereas no such lead-time to pay their dues has been allowed in the case of users. This differentiation has had to be made in recognition of the fact that the MPT Act requires the users to pay the applicable charges before availing port services or before obtaining port-clearance certificate, as the case may be.
- (iii). As has been brought out in the proposal of the MOPT, and in the comments furnished by the PPT, there are certain services for which bills are raised post-operation. In such cases, there is a need to allow some lead-time to users to make payments. The MBPT's comments that it was allowing a grace period to users for payment of bills before implementation of this Authority's Order dated 4 February 2000 are significant in this context.

A grace period for payment of bills by the users, if allowed, can only be confined to the cases where bills are raised post-operation by the Ports. It cannot be made applicable to those cases where payment is to be made before availing the services / using the Port Trust's properties as stipulated in the MPT Act or where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the Scale of Rates.



- (iv). Most of the major ports have agreed with the proposal of the MOPT to allow a grace period to users.

As pointed out by the VPT and the KPT, allowing a grace period from the date of receipt of bill by users will be cumbersome, as such a detail cannot be easily captured by the Ports. As suggested by these ports, counting the grace period from the date of raising such bills by the ports appears to be more practical.

- (v). The MOPT has revised its earlier proposal to suggest that the grace period may be counted only in terms of working days. The MBPT's observation in this regard is relevant and reasonable. For the sake of simplicity, the grace period may be prescribed in terms of calendar days instead of working days. It is relevant here to mention that the lead-time allowed to the Port Trusts for refunds is only 20 days and not 20 working days.

- (vi). The MOPT has proposed a grace period of seven working days from the date of receipt of bills by users. Since the grace period is now proposed to be counted in terms of calendar days starting from the date of raising the bills by Ports, it will be reasonable to allow a grace period of 10 days, as suggested by the MBPT and the NMPT.

- (vii). The CPT's understanding about the grace period is not correct. There is no need to extend any grace period to the Ports to process refund claims as a lead time of 20 days has already been prescribed in their cases. Likewise, the CPT's arguments that penal interest is for opportunity cost and, therefore, it shall be equal to the interest rate on Savings Bank account are totally misplaced. Penal interest is a deterrent measure to ensure timely payments / refunds; and, therefore, the interest rate must be at such level that will really act as a penalty for defaulters.

The issue of prescribing a penal interest rate has already been settled; and hence, there is no need to review the rate already prescribed.

6.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the insertion of the following prescription under paragraph 3 of its Order dated 4 February 2000 (partially amended by Order dated 16 May 2001):

- “(iv). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the Port Trusts. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services / use of Port Trust's properties as stipulated in the MPT Act and / or where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the Scale of Rates.”

6.2. This Order will come into effect immediately after its notification in the Gazette of India.

6.3. All the Major Port Trusts are required to introduce appropriate changes in their Scale of Rates to incorporate the above prescription.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT. III/TV/143/2001/Ext.]

2876 61/2001-3

